इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह लागू होने से देश में कुल टोल संग्रह कम-से-कम 10,000 करोड़ रुपए बढ़ जाएगा।

नितिन गडकरी, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री

सेंसेक्स 78,053 (712.44) | निफ्टी 23,721 (183.45) | डॉलर 1$ = 83.43 (0.04) | सोना 72,550 (70) | चांदी टंच 91,500 (400)

प्रोत्साहन योजना के दायरे में परिधान क्षेत्र को भी लाने पर विचार: गिरिराज सिंह

कपड़ा उद्योग को आने वाले वर्षों में 50 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के निर्यात का लक्ष्य रखना चाहिए

नई दिल्ली। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, द्वारका में इंडिया इंटरनेशनल गारमेंट फेयर (आईआईजीएफ) के 71वें संस्करण के उद्घाटन के मौके पर एक महिला से चर्चा करते हुए।

एजेंसी • नई दिल्ली

editor@peoplessamachar.co.in

कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने कपड़ा उद्योग के लिए स्वीकृत 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की 'उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना' का विस्तार परिधान क्षेत्र तक करने पर भी विचार कर रही है। सिंह ने यहां भारत अंतरराष्ट्रीय परिधान मेला (आईआईजीएफ) को संबोधित करते हुए कहा कि कपड़ा निर्यात बढ़ाने के लिए अपार अवसर हैं और उद्योग को आने वाले वर्षों में 50 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के निर्यात का लक्ष्य रखना चाहिए।

सरकार ने वर्ष 2021 में मानव-निर्मित रेशे (एमएमएफ) से बने परिधान, एमएमएफ कपड़े और तकनीकी वस्त्रों के उत्पादों का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए पांच साल की अवधि में 10,683 करोड़ के स्वीकृत परिव्यय के साथ कपड़ा क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दी थी। सिंह ने कहा कि हम आपके (परिधान) क्षेत्र को भी इस योजना के दायरे में लाने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय कपड़ा उद्योग का बाजार लगभग 165 अरब डॉलर का है और इसे 350 अरब डॉलर तक ले जाना है। मंत्रालय इस क्षेत्र में चीन से आगे निकलने के लिए एक रूपरेखा तैयार कर रहा है। मंत्री ने उद्योग को घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 'हब और स्पोक' मॉडल को अपनाने का सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा, मैं उद्योग की बड़ी कंपनियों से भारत में छोटी कंपनियों के साथ जुड़ाव कायम करने की अपील करता हूं।

रेमंड अपनी परिधान क्षमता को एक-तिहाई बढ़ाने में जुटी: सिंघानिया

अग्रणी परिधान विनिर्माता रेमंड अपनी क्षमता में एक-तिहाई का विस्तार कर रही है, जिससे वह दुनिया में सूट की तीसरी बड़ी उत्पादक बन जाएगी और वैश्विक बाजार में स्थिति मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। कंपनी नए बाजारों के लिए अपने उत्पादों की शृंखला का विस्तार करेगी और ग्राहकों की संख्या बढ़ाने पर भी काम कर रही है। उसके कारोबार में महिला परिधानों की सिलाई और महंगे दाम वाले कैजुअल कपड़े भी शामिल हैं। रेमंड की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया गया है।

निर्यात बढ़ाने के उपायों पर गोयल निर्यातकों के साथ करेंगे बैठक

नई दिल्ली। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल देश के निर्यात को गति देने के उपायों पर चर्चा के लिए विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। उद्योग के एक अधिकारी ने कहा कि निर्यात संगठनों के शीर्ष निकाय फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (फियो) और चमड़ा निर्यात परिषद सहित निर्यात संगठनों के प्रतिनिधि बैठक में भाग लेंगे। निर्यात परिषद के एक अधिकारी के अनुसार वे बैठक में ब्याज छूट योजना को आगे बढ़ाये जाने, चमड़ा और जूता-चप्पल क्षेत्र के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना तथा कुछ क्षेत्रों में सीमा शुल्क में बदलाव का आग्रह समेत अन्य मामले रखेंगे।

बिजनेस न्यूज

सोने में 70 रुपए की तेजी, चांदी 400 रुपए टूटी

नई दिल्ली। राजधानी के सराफा बाजार में मंगलवार को सोना 70 रुपए की तेजी के साथ 72,550 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। हालांकि, चांदी की कीमत पिछले बंद भाव के मुकाबले 400 रुपए की गिरावट के साथ 91,500 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई। पिछले कारोबारी सत्र में यह 91,900 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के शोध विश्लेषक सौमिल गांधी ने कहा कि दिल्ली के बाजारों में हाजिर सोने (24 कैरेट) की कीमतें 72,550 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रही थीं। यह पिछले बंद भाव से 70 रुपए अधिक है।

अमारा राजा एनर्जी-मोबिलिटी का शेयर 19 प्रतिशत चढ़ा

नई दिल्ली। अमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड का शेयर मंगलवार को 19 प्रतिशत चढ़कर बंद हुआ। इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई अमारा राजा एडवांस्ड सेल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के लिथियम-आयन सेल प्रौद्योगिकी के लिए जीआईबी एनजीएक्स स्लोवाकिया एसआरओ के साथ लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद कंपनी के शेयरों में उछाल आया। बीएसई पर दिन के कारोबार में कंपनी का शेयर 19.99 प्रतिशत बढ़कर 52 सप्ताह के उच्चस्तर 1,655.20 रुपए पर पहुंच गया।

सेल्सफोर्स को 2028 तक 18 लाख नौकरियों की उम्मीद

मुंबई। सीआरएम कंपनी सेल्सफोर्स को भारत में इसके ग्राहकों और भागीदारों के इकोसिस्टम से 2022 से 2028 तक 18 लाख नई नौकरियों और 88.6 अरब डॉलर के कारोबारी राजस्व मिलने की उम्मीद है। आईडीसी सेल्सफोर्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट अध्ययन में यह बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि आर्थिक विकास को गति देने में एआई-संचालित क्लाउड सॉल्यूशंस परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में उभर रही है।

स्टार्टअप सिड्स फार्म ने एक करोड़ डॉलर जुटाए

नई दिल्ली। डेयरी स्टार्टअप सिड्स फार्म ने मंगलवार को कहा कि उसने अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए निवेशकों से एक करोड़ डॉलर जुटाए हैं। सिड्स फार्म ने उच्च गुणवत्ता वाले डेयरी उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाकर हैदराबाद और बेंगलुरु में एक मजबूत उपस्थिति स्थापित करने के लिए इस कोष का उपयोग करने की योजना बनाई है।

बजट पूर्व चर्चा में उद्योगपति दे रहे सुझाव

चमड़ा, जूता-चप्पल निर्यातकों की बजट में पीएलआई योजना लाने की मांग

एजेंसी • नई दिल्ली

editor@peoplessamachar.co.in

चमड़ा और फुटवियर निर्यातकों के संगठन ने मंगलवार को सरकार से रोजगार सृजन, घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का विस्तार चमड़ा उद्योग तक करने की मांग की। चमड़ा निर्यात परिषद (सीएलई) के चेयरमैन राजेंद्र कुमार जालान ने यहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट-पूर्व बैठक में यह मांग रखी।

जालान ने कहा कि पीएलआई योजना को लागू करने से चमड़ा उद्योग का संरचनात्मक बदलाव होगा और देश एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र बन जाएगा। इसके साथ ही सीएलई ने सरकार से नम नीले चमड़े, क्रस्ट चमड़े और तैयार चमड़े पर आयात शुल्क में छूट देने का भी आग्रह किया। जालान ने कहा कि पीएलआई न केवल क्षमता आधुनिकीकरण और मौजूदा इकाइयों के विस्तार बल्कि स्टार्टअप में भी घरेलू एवं विदेशी निवेश को बढ़ावा देगा, जिससे समग्र उत्पादन आधार का विस्तार होगा। उन्होंने कहा, पीएलआई के लाभ में 6,000 करोड़ का वृद्धिशील निवेश और प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 20 लाख श्रम कार्यबल का अतिरिक्त रोजगार सृजन शामिल होगा। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में नम नीले चमड़े, क्रस्ट और तैयार चमड़े का आयात 45.07 करोड़ डॉलर का था।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में आगामी केंद्रीय बजट 2024-25 के लिए सुझाव लेने के लिए रोजगार और कौशल प्रभाग के प्रतिनिधियों के साथ आठवें प्री-बजट परामर्श की अध्यक्षता की।

सोने, चांदी, प्लेटिनम बार पर आयात शुल्क घटाने की मांग

रत्न और आभूषण निर्यातकों ने बजट में सोने, चांदी और प्लेटिनम बार पर आयात शुल्क घटाकर चार प्रतिशत करने की मांग की। वित्त मंत्री के साथ यहां बजट पूर्व बैठक में रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद ने कहा कि भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग कुल वस्तु निर्यात में लगभग 10 प्रतिशत का योगदान देता है। उन्होंने कहा कि हालांकि, उद्योग इस समय भू-राजनीतिक परिदृश्य, लाभकारी योजना और कच्चे हीरे की सोर्सिंग से जुड़े मुद्दों के कारण कुछ चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे हालात में परिषद ने सरकार से इस क्षेत्र में निर्यात को पुनर्जीवित करने के लिए उपाय करने का आग्रह किया। उद्योग ने सोने, चांदी और प्लैटिनम पर आयात शुल्क घटाकर चार प्र. करने और भारत-यूएई व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते का लाभ उठाने के लिए प्लैटिनम आभूषणों के निर्यात पर शुल्क वापसी योजना पेश करने की मांग की।

बैठक में ट्रेड और सेवा क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव दिये और विचार रखे

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को यहां आम बजट 2024-25 की तैयारियों के मद्देनजर ट्रेड और सेवा क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ ही रोजगार एवं कौशल विकास क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ बजट-पूर्व चर्चा की। वित्त मंत्रालय ने एक्स पर यह जानकारी देते हुए कहा कि इस बैठक में ट्रेड और सेवा क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव दिये और विचार रखे। इसके साथ ही आज की दूसरी बैठक में वित्त मंत्री ने रोजगार एवं कौशल विकास क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ बजट को लेकर चर्चा की। वित्त मंत्री ने इन बैठकों की अध्यक्षता की। बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त सचिव; आर्थिक मामलों के सचिव, राजस्व सचिव, वित्तीय सेवाओं के सचिव के साथ ही वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी इसमें शामिल हुए। रोजगार एवं कौशल विकास क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ चर्चा के दौरान श्रम मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमशिलता मंत्रालय के अधिकारियों ने भी भाग लिया। उल्लेखनीय है कि आम चुनाव में मद्देनजर इसबार फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया गया था।

स्पेक्ट्रम नीलामी के पहले दिन करीब 11,000 करोड़ रुपए की बोलियां लगीं

नई दिल्ली। दूरसंचार कंपनियों ने स्पेक्ट्रम नीलामी के पहले दिन मंगलवार को पांच दौर में करीब 11,000 करोड़ रुपए मूल्य की बोलियां लगाईं। सूत्रों ने यह जानकारी दी। सरकार 96,238 करोड़ रुपए के आरक्षित मूल्य पर 10,500 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी कर रही है। इसके लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से बोलियां आमंत्रित की गई हैं। मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने कहा कि दूरसंचार कंपनियों ने पहले दिन की स्पेक्ट्रम नीलामी में करीब 11,000 करोड़ रुपए की बोलियां लगाई हैं। नीलामी बुधवार को फिर शुरू होगी। दूरसंचार विभाग की तरफ से पहले दिन की नीलामी के बारे में जारी रिपोर्ट के मुताबिक, बोलियां मुख्य रूप से 900 और 1,800 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम के बैंड में लगाई गई हैं। इस नीलामी में रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया शिरकत कर रही हैं। रिलायंस जियो ने स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए सबसे अधिक 3,000 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि जमा की है। इस आधार पर कंपनी अधिकतम रेडियो तरंगों के लिए बोली लगा सकती है। भारती एयरटेल ने 1,050 करोड़ रुपए और वोडाफोन आइडिया (वीआईएल) ने 300 करोड़ रुपए की बयाना राशि जमा की है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, स्पेक्ट्रम नीलामी सुबह 10 बजे शुरू हुई और धीरे-धीरे इसके कुल पांच दौर आयोजित हुए। स्पेक्ट्रम की बिक्री प्रक्रिया 2010 में ऑनलाइन शुरू होने के बाद से यह 10वीं नीलामी है। आखिरी बार अगस्त, 2022 में स्पेक्ट्रम नीलामी हुई थी, जिसमें पहली बार 5जी सेवाओं के लिए रेडियो तरंगों की पेशकश की गई थी।

भारत में 80 प्रतिशत सीमांत किसान प्रतिकूल जलवायु से प्रभावित : रिपोर्ट

एजेंसी • नई दिल्ली

editor@peoplessamachar.co.in

पिछले पांच वर्षों में प्रतिकूल जलवायु घटनाओं के कारण भारत में 80 प्रतिशत सीमांत किसानों को फसल का नुकसान उठाना पड़ा है। डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट (डीआईयू) के सहयोग से फोरम ऑफ एंटरप्राइजेज फॉर इक्विटेबल डेवलपमेंट (एफईईडी) द्वारा किए गए सर्वेक्षण में 21 राज्यों के 6,615 किसान शामिल थे। सर्वेक्षण के निष्कर्षों से पता चलता है कि फसल के नुकसान के प्राथमिक कारण सूखा (41 प्रतिशत), अत्यधिक या गैर-मौसमी बारिश सहित अनियमित वर्षा (32 प्रतिशत) और मानसून का समय से पहले वापस लौटना या देर से आना (24 प्रतिशत) है। रिपोर्ट के अनुसार, सर्वेक्षण में शामिल लगभग 43 प्रतिशत किसानों ने अपनी खड़ी फसलों का कम से कम आधा हिस्सा गंवा दिया। असमान वर्षा से चावल, सब्जियां और दालें विशेष रूप से प्रभावित हुईं। उत्तरी राज्यों में, धान के खेत अक्सर एक सप्ताह से अधिक समय तक जलमग्न रहते हैं, जिससे नए रोपे गए पौधे नष्ट हो जाते हैं। इसके विपरीत महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में कम बारिश के कारण चावल, मक्का, कपास, सोयाबीन,दालों जैसी विभिन्न फसलों की बुवाई में देरी हुई है।

शाओमी का युवराज फाउंडेशन के साथ स्तन कैंसर जांच अभियान, डेढ़ लाख महिलाओं की जांच होगी

एजेंसी • नई दिल्ली

editor@peoplessamachar.co.in

इनोवेशन और सामुदायिक कल्याण में योगदान देते हुए दस साल पूरे करने के अवसर पर टेक्नोलॉजी कंपनी शाओमी इंडिया ने क्रिकेटर और कैंसर सर्वाईवर युवराज सिंह द्वारा स्थापित युवराज सिंह फाउंडेशन (यूवीकैन) के साथ साझेदारी की है जिसके तहत देश के 15 राज्यों में एक साल में 1.5 लाख स्तन कैंसर पीड़ित महिलाओं की जांच की जाएगी। कंपनी ने कहा कि इसके अंतर्गत 'स्वस्थ महिला, स्वस्थ भारत' प्रोजेक्ट द्वारा वंचित और संसाधनों की कमी वाली महिलाओं की जांच की जाएगी। अभियान भारत में प्रभाव और पहुँच के मामले में शाओमी का अब तक का सबसे विशाल प्रयास है।

शाओमी इंडिया के अध्यक्ष मुरलीकृष्णन बी ने कहा, भारत में हमारे एक दशक के सफर में हम सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए अपने विस्तृत नेटवर्क का उपयोग कर एक टेक्नोलॉजी ब्रांड के मुकाबले काफी आगे तक विकास कर गए हैं। कड़वी सच्चाई यह है कि भारत में स्तन कैंसर के कारण हर 6 मिनट में एक महिला की मौत होती है, जिनमें से 70 प्रतिशत मामलों में निदान जाँच की कमी के कारण काफी एडवांस्ड स्टेज में होता है। इससे प्रदर्शित होता है कि हमारा यह मिशन कितना महत्वपूर्ण है। हमें युवराज सिंह फाउंडेशन (यूवीकैन) के साथ मिलकर काम करने पर गर्व है।

जेएसडब्ल्यू स्टील 11 करोड़ डॉलर का करेगी निवेश

नई दिल्ली। जेएसडब्ल्यू स्टील की अनुषंगी कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील यूएसए टेक्सास के बेयटाउन में अपनी स्टील प्लेट मिल को नए उपकरणों और टिकाऊ प्रौद्योगिकी के साथ आधुनिक बनाने के लिए 11 करोड़ डॉलर का निवेश करने की योजना बना रही है। कंपनी के अनुसार, इस निवेश से उच्च गुणवत्ता वाले मोनोपाइल स्टील प्लेट का उत्पादन संभव होगा, जिससे अपतटीय पवन ऊर्जा के विस्तार के लिए अमेरिकी प्रशासन के नए कदमों को समर्थन मिलेगा। इसके लिए 2030 तक 30 गीगावाट (जीडब्ल्यू) अपतटीय पवन ऊर्जा की स्थापना की जाएगी, जो एक करोड़ मकानों को स्वच्छ ऊर्जा से बिजली प्रदान करने के लिए पर्याप्त होगी।

फार्म ए

सार्वजनिक सूचना

(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 6 के अंतर्गत

केसर मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक लिमिटेड के लेनदारों के ध्यान के लिए

	प्रासंगिक विवरण	
1.	कॉर्पोरेट देनदार का नाम	केसर मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	30/09/2011
3.	प्राधिकरण जिसके तहत कॉर्पोरेट देनदार निगमित / पंजीकृत है	आरओसी-मुम्बई
4.	कॉर्पोरेट देनदार की सीमित देयता पहचान संख्या/कार्पोरेट पहचान संख्या	U74120MH2011PLC222597
5.	कॉर्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय और प्रमुख कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	रजि. पता : ओरिएन्टल हाउस, 7, जमशेदजी टाटा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020 महाराष्ट्र भारत
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में दिवाला शुरू होने की तारीख	21.06.2024 (आदेश दिनांक 21.06.2024 की प्रति अंतरिम समाधान पेशेवर को 24.06.2024 को प्राप्त हुई थी।)
7.	दिवालिया समाधान प्रक्रिया बंद होने की तिथि	18.12.2024। (21.06.2024 से 180 दिन होने के कारण)
8.	परिसमापक के रूप में कार्य करने वाले दिवाला पेशेवर की पंजीकरण संख्या तथा नाम	श्री प्रशांत जैन रजि.नं. (IBBI/IPA-001/IP-P01368/2018-2019/12131)
9.	परिसमापक का पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड के साथ पंजीकृत है	रजि. पता : ए501, शांति हाईट्स, प्लाट नं.2, 3, 9, बी/10, सेक्टर 11,कोपरखरीने, ठाणे, नवी मुम्बई महाराष्ट्र-400 709 ईमेल : ipprashantjain@gmail.com
10.	परिसमापक के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किया जाने वाला पता और ई-मेल,	सी/ओ एससार्वी रिसॉल्यूशन सर्विसेस एलएलपी बी/610, बीएसईएल टेकपार्क, वाशी रेलवे स्टेशन के सामने, वाशी, नवी मुम्बई- 400 703 वेबसाईट :www.ssarvi.com/ ईमेल : kmll.cirp@gmail.com
11.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	08/07/2024 (24.06.2024 से 14 दिन होने के कारण)
12.	लेनदारों के वर्ग, यदि कोई हो, धारा 21 की उप-धारा (6ए) के खंड (बी) के तहत, अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा निर्धारित किया गया	लागू नहीं
13.	एक वर्ग में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए पहचाने गए दिवाला पेशेवरों के नाम (प्रत्येक वर्ग के लिए तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(अ)प्रासंगिक फार्म्स एवं (ब)अधिकृत प्रतिनिधि का विवरण यहां उपलब्ध है:	https://www.ibbi.gov.in/home/downloads लागू नहीं

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने केसर मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक लिमिटेड का कार्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया का आदेश दिया है एवं दिनांक 21.06.2024। (आदेश दिनांक 24.06.2024 की प्रति अंतरिम समाधान पेशेवर को को प्राप्त हुई थी।)

केसर मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक लिमिटेड के लेनदारों, को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 08.07.2024 या उससे पहले अंतरिम रिजॉल्यूशन पेशेवर द्वारा प्रविष्टि संख्या 10 के विरूद्ध उल्लेखित पते पर प्रमाण के साथ अपने दावों को प्रस्तुत करें।

वित्तीय लेनदारों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रमाण के साथ अपने दावे प्रस्तुत करेंगे। अन्य सभी लेनदारों को अपने दावे प्रमाण के साथ व्यक्ति, डाक से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने दावों को प्रस्तुत करें।

दावे के झूठे या भ्रामक सबूत प्रस्तुत करना दंड को आकर्षित करेगा।

दिनांक : 26/06/2024
स्थानः मुम्बई

हस्ते/-
श्री प्रशांत जैन
रजिस्ट्रेशन नं. : IBBI/IPA-001/IP-P01368/2018-2019/12131
एएफए 24 सितम्बर 2024 तक वैध
अंतरिम रिजाल्यूशन प्रोफेशनल
केसर मल्टीमोडल लॉजिस्टिक लिमिटेड

एचडीएफसी बैंक ने कर्मचारियों के लिए 'फ्रॉड अवेयरनेस सेशन' आयोजित किया

एजेंसी • मुंबई

editor@peoplessamachar.co.in

एचडीएफसी बैंक ने सुरक्षित बैंकिंग जागरूकता अभियान के तहत अपने कर्मचारियों के लिए एक वर्चुअल 'फ्रॉड अवेयरनेस सेशन' आयोजित किया। इस सत्र का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की धोखाधड़ी प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना और कर्मचारियों को धोखेबाजों की रणनीतियों के बारे में अधिक जागरूक होने के लिए जानकारी और कौशल से लैस करना था। सुंदरेसन एम, समूह प्रमुख - खुदरा ऋण रणनीति व नियंत्रण और मनीष अग्रवाल, कायर्कारी उपाध्यक्ष - क्रेडिट इंटेलिजेंस व नियंत्रण - एचडीएफसी बैंक ने इस कार्यक्रम की मेजबानी की और इसे और स्पष्ट करने के लिए केस स्टडी साझा की। सेशन में कर्मचारियों को कूरियर घोटाले, फर्जी पुलिस घोटाले, फर्जी क्रेडिट घोटाले जैसे नए प्रकार के धोखाधड़ी के बारे में शिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। साथ ही धोखाधड़ी वाले खाते खोलने से कैसे बचें, मनी म्यूल(एस), टेरोरिस्ट फंडिंग, साइबर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के लिए बैंकिंग चैनलों के दुरुपयोग को कैसे रोकें जैसे पहलुओं को सभी कानूनी और प्रतिष्ठा संबंधी परिणामों के साथ शामिल किया गया।

किडजानिया थीम पार्कों में एयर इंडिया एविएशन एकेडमी

एजेंसी • नोएडा

editor@peoplessamachar.co.in

विमानन कंपनी एयर इंडिया ने शैक्षिक व मनोरंजन ब्रांड किडजानिया के साथ मिलकर किडजानिया के नोएडा एवं मुंबई स्थित थीम पार्कों में एयर इंडिया ऐविएशन एकेडमी लांच करने की घोषणा की है। इस अकेडमी में बच्चे एक मॉडल एयरक्राफ्ट के भीतर पायलट व केबिन क्रू की भूमिकाएं निभाते हुए ऐविएशन इंडस्ट्री में कॅरियर बनाने संबंधी जानकारी प्राप्त करेंगे। एकेडमी में बच्चे एयर इंडिया की फ्लीड का मॉडल देखेंगे, उसकी

सुविधाओं, नई ब्रांडिंग, रंगों व पोशाक के बारे में जानेंगे। इसका लक्ष्य है बच्चों को इंट्रैक्टिव और दिलचस्प रोल-प्ले गतिविधियों के जरिए ऐविएशन इंडस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अनूठा अवसर दिया जाए। इस सहयोग के माध्यम से एयर इंडिया और किडजानिया का उद्देश्य है एक मंच मुहैया करा कर ऐविएशन के उत्साहियों और पेशेवरों की नई पीढ़ी को विकसित किया जाए। यहां आकर बच्चे वास्तविक पेशेवरों की तरह भूमिकाएं अदा कर के जान व सीख सकेंगे जैसे पायलट द्वारा हवाई जहाज उड़ाना और केबिन क्रू की तरह काम करना। एकेडमी की कोशिश है बच्चों में साइकोमीटर, संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं सामाजिक कौशल को मजबूत करना। किडजानिया में एयर इंडिया ऐविएशन एकेडमी को इसलिए बनाया गया है ताकि बच्चे इन गतिविधियों में शामिल होकर जान पाएं की हकीकत में ऐविएशन का काम किस तरह से होता है।